

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

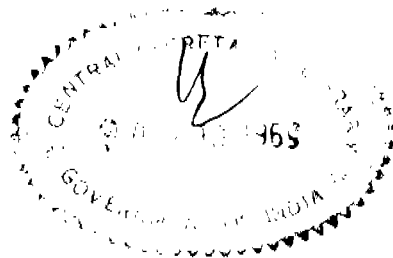
EXTRAORDINARY

भाग I —खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 32] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 22, 1969/चैत्र 1, 1891

No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 22, 1969/CHAITRA 1, 1891

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

### RESOLUTION

New Delhi, the 22nd March 1969

No. F. 1(63)-B/68.—The Government of India is pleased to constitute a Team consisting of the following officers to consider certain matters relating to Accounts and Budget Heads arising out of the recommendations of the Administrative Reforms Commission in its Report on "Finance, Accounts and Audit" and "The Machinery of the Government of India and its procedures of work":—

1. Shri A. K. Mukherji, Deputy Comptroller & Auditor General (Convenor).
2. Shri A. R. Shirali, Joint Secretary (Budget).
3. Shri V. M. Bhide, Joint Secretary (Planning Commission) will be co-opted as and when matters relating to Plan Heads of Development are considered.
4. An officer of the Administrative Ministry concerned will be co-opted as and when matters relating to that Ministry are considered.

2. The terms of reference to the Team will be as follows:

- (a) (i) To conduct a comprehensive review of the Heads of Accounts and the Heads of Development adopted for Plan purposes on the lines indicated in recommendation No. 2 of the Administrative Reforms Commission's Report on 'Finance, Accounts and Audit' keeping in view the requirements of performance budgeting and the economic classification of the budget; and
- (ii) to make recommendations for establishing a direct correlation between the Plan Heads of Development and the Heads of Accounts and also between programmes and activities of departments and organisations where performance budgeting is to be introduced and minor heads or subheads of accounts,

While making recommendations on (ii) above the Team will have due regard to recommendation No. 1 of the Report of the Administrative Reforms Commission on 'Finance, Accounts and Audit'.

- (b) (i) To consider recommendation No. 16 of the Administrative Reforms Commission's Report on 'Finance, Accounts and Audit'; and
- (ii) to recommend measures for streamlining the primary units of appropriation and for making the Demands for Grants and the corresponding central accounts more compact and comprehensive, keeping also in view recommendation No. 13 of the Report of the Administrative Reforms Commission on the "Machinery of the Government of India and its procedures of work" in so far as it relates to the need for making distinct provision in the budget for each wing of a Ministry;
- (c) (i) to review in the context of recommendation No. 17 of the Administrative Reforms Commission's Report on 'Finance, Accounts and Audit' the working of the scheme of separation of accounts from audit as introduced in certain Departments in recent years; and
- (ii) to recommend measures in the direction of maintenance of appropriate accounts within the various Departments of Government as an aid to management;
- (d) (i) to study the practical aspects of recommendation No. 18 of the Administrative Reforms Commission's Report on "Finance, Accounts and Audit"; and
- (ii) to make specific recommendations regarding the detailed accounts which should be maintained by the various Departments of Government and the extent to which the details could be eliminated from the accounts maintained in the offices of the Accountants General and other Accounts Offices;
- (e) to review the heads of accounts in the Public Account of the Union and to make recommendations in this regard; and
- (f) to consider any other specific matter that may be referred to the Team by Government.

3. The Team shall submit recommendations to Government by 31st March, 1970.

#### ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the Convenor and Members of the Team.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. R. SHIRALI, Jt. Secy.

## वित्त मंत्रालय

## (अर्थ विभाग)

## संकल्प

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1969

संख्या एक० 1 (65)-बी/68.---भारत सरकार प्रशासनिक सुधार आयोग की “वित्त, लेखा और लेखा-परीक्षा” और “भारत सरकार के तन्त्र और उसकी कार्यप्रणालियाँ” सम्बन्धी रिपोर्टों में की गयी सिफारिशों से पैदा होने वाले लेखा-शीर्षकों और बजट शीर्षकों से सम्बद्ध कुछ मामलों पर विचार करने के लिए सहर्ष एक दल का गठन करती है जिसके सदस्य निम्नलिखित अधिकारी होंगे :

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. श्री ए० के० मुखर्जी, | उप-नियंत्रक महालेखा परीक्षक (संयोजक)  |
| 2. श्री ए० आर० शिराली,  | संयुक्त सचिव (बजट)  |
| 3. श्री बी० एम० भिडे,   | संयुक्त सचिव (योजना आयोग) (जब विकास के आयोजना सम्बन्धी शीर्षकों से सम्बद्ध मामलों पर विचार किया जाएगा तब इन्हें सहयोजित किया जायगा) |

4. सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय का एक अधिकारी सहयोजित किया जाएगा जब उस मंत्रालय के सम्बन्ध में मामलों पर विचार किया जायगा।

2. दल के विचारणीय विषय ये होंगे :

- (क) (i) कार्य-सम्बन्धी बजट तैयार करने और बजट का आर्थिक वर्गीकरण तैयार करने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए “वित्त, लेखा और लेखा-परीक्षा” के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट की दूसरी सिफारिश में निर्दिष्ट तरीकों के अनुसार लेखा शीर्षकों और आयोजना के उद्देश्यों के लिए अपनाये गये विकास के शीर्षकों की व्यापक समीक्षा करना; और
- (ii) विकास के आयोजना सम्बन्धी शीर्षकों और लेखा-शीर्षकों के बीच और इसके साथ-साथ उन विभागों और संगठनों के कार्यक्रमों तथा लेखों के लघु-शीर्षकों या उप-शीर्षकों के बीच परस्पर प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सिफारिशें करना जिनके लिए कार्य-सम्बन्धी बजट तैयार करने का काम शुरू किया जाना है।”

उपर्युक्त मद (ii) के सम्बन्ध में सिफारिशें करते समय दल प्रशासनिक सुधार आयोग की “वित्त, लेखा और लेखा-परीक्षा” सम्बन्धी रिपोर्ट की पहली सिफारिश का भी उचित रूप से ध्यान रखेगा।

- (ख) (i) प्रशासनिक सुधार आयोग की “वित्त, लेखा और लेखा-परीक्षा” सम्बन्धी रिपोर्ट की सोलहवीं सिफारिश पर विचार करना; और

- (ii) प्रशासनिक सुधार आयोग की “भारत सरकार के तन्त्र और उसकी कार्य-प्रणालियाँ सम्बन्धी रिपोर्ट की तेरहवीं सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, जहाँ तक कि इसका सम्बन्ध किसी मंत्रालय की प्रत्येक प्रशाखा के लिए बजट में अलग से व्यवस्था करने से है, विनियोग की प्रारम्भिक मर्कों को सरल बनाने और अनुदानों की मर्गों तथा तदनु रूप केन्द्रीय लेखों को और अधिक संक्षिप्त तथा व्यापक बनाने के लिए उपायों की सिफारिश करना;
- (ग) (i) प्रशासनिक सुधार आयोग की “वित्त, लेखा और लेखा-परीक्षा” सम्बन्धी रिपोर्ट की सत्रहवीं सिफारिश को ध्यान में रखते हुए हाल के वर्षों में, कुछ विभागों में लेखा-पालन को लेखा-परीक्षा से अलग करने के लिए शुरू की गयी योजना के काम की प्रगति की समीक्षा करना : और
- (ii) सरकार के विभिन्न विभागों में, प्रबन्ध कार्य में सहायता प्रदान करने के उपाय के रूप में, सही तौर पर लेखे रखने की दिशा में उठाये जाने वाले कदमों की सिफारिश करना;
- (घ) (i) प्रशासनिक सुधार आयोग की “वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा” सम्बन्धी रिपोर्ट की अठारहवीं सिफारिश के व्यावहारिक पहलुओं का अध्ययन करना; और
- (ii) सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा रखे जाने वाले सविस्तार लेखों और महालेखाकारों के कार्यालयों तथा लेखा-कार्यालयों में रखे जाने वाले लेखों में से निकाले जाने वाले विवरणों की सीमा के सम्बन्ध में खास खास सिफारिशें करना; और
- (ङ) केन्द्र के सार्वजनिक लेखों के लेखा-शीर्षकों की समीक्षा करना और इस सम्बन्ध में सिफारिशें करना; और
- (च) सरकार द्वारा दल को सौंपे जाने वाले किसी अन्य विशेष मामले पर विचार करना ।

3. दल 31 मार्च, 1970 तक सरकार के सामने अपनी सिफारिशें पेश कर देगा ।

### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को एक प्रति दल के संयोजक और सदस्यों को भज दी जाय ।

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्वसाधारण की सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

ए० आर० शिराली,  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।